बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 68 ● नई दिल्ली ● सोमवार 22 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

क्षतिग्रस्त भवन में प्रवेश के बताये तरीके

मुरादाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा उ0 प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र के पंचम दिन प्रशिक्षण सत्र में सर्वप्रथम इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना की गई । तत्पश्चात श्री नीरज चक्र, उपनियंत्रक द्वारा पहले सेशन में क्षतिग्रस्त भवन में प्रवेश आदि के बारे में बताया गया । दूसरे सेशन में श्री मो0 हारून, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे संरचना और खोज आदि को समझाया गया। फायरमैन लोकेश कुमार और कामेंद्र सिंह के द्वारा सभी प्रशिक्षक भारतीयों को हाई प्रेशर पंप से बड़ी आग और फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से छोटी आग बुझे जाते समय उपकरणों का प्रयोग उनको जांचना उनका प्रयोग में लाते समय सावधानियां बरतना आदि विस्तृत रूप से समझाया गया और उसके बाद लाइव डेमो कराते समय उपकरणों का प्रयोग भी करवाया गया।

जहरीली हवा से सांसों पर संकट... अभी राहत के आसार नहीं, गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंची हवा

नई दिल्ली । राजधानी में स्थानीय कारकों के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हवा की गति धीमी होने के चलते लगातार छठे दिन भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, रविवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 393 दर्ज किया गया है। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। इससे पहले शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 398 दर्ज किया गया। रविवार को यानी आज हवा के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 375, आनंद विहार में एक्यूआई 426, अशोक विहार में 425, आया नगर में 309, बवाना में 439, बुराड़ी में 378, चांदनी चौक इलाके में 448 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

वहीं, डीटीयू में 433, द्वारका सेक्टर 8 इलाके में 408, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 332, आईटीओ में 393, जहांगीरपुरी में 438, लोधी रोड 357, मुंडका 433, नजफगढ़ में 371, पंजाबी बाग में 420, आरकेपुरम 394, रोहिणी 433,

सोनिया विहार 410, विवेक विहार 413, वजीरपुर में 443 दर्ज किया गया है। दिल्ली में दिसंबर की ठंड के साथ इस बार जहरीली हवा ने भी लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि राजधानी में सांस लेना भी चुनौती जैसा महसूस हो रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर की शुरुआत से ही दिल्ली की हवा लगातार खराब बनी हुई है और पहले 18 दिनों में ही इसने बीते आठ साल की सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया। महीने की शुरुआत से ही हालात ऐसे रहे कि ज्यादातर दिनों में हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी रही। दिसंबर के पहले आठ दिनों तक लगातार एक्यूआई 300 से ऊपर रहा जिससे पूरे महीने का औसत एक्यूआई करीब 343 तक पहुंच गया। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 14 दिसंबर को एक्यूआई 461 दर्ज किया गया, जो बीते आठ वर्षों में दिसंबर महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। हवा के बिगड़ते हालात को देखते हुए 13 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) का सबसे सख्त चरण, यानी स्टेज-चार लागू करना पड़ा।

दिल्ली के नालों में सफाई और जल निकासी पर महापौर की सख्त चेतावनी, नागरिकों को राहत की उम्मीद

नई दिल्ली। दिल्ली में जलभराव और गंदगी की पुरानी समस्या को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने गोकलपुर ड्रेन का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि सफाई में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. इस दौरान विधायक अजय महावर, डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर, पार्षद रेखा रानी और प्रीति गुप्ता भी उपस्थित रहीं. इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त लीलाधर मेघवाल, निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा सहित नगर निगम और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य गोकलपुर ड्रेन में चल रहे सफाई कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था. इसके साथ ही जल निकासी की व्यवस्था की समीक्षा की गई और लंबे समय से बनी जलभराव एवं गंदगी की समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा हुई. निरीक्षण

खजूरी चौक नाला से लेकर पांचवें पुस्ते नाला तक किया गया, जहां सिल्ट, कचरा निष्कासन और जल प्रवाह की स्थिति को बारीकी से देखा गया.

अधिकारियों को सख्त निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नालों की सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. सफाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए. समयबद्ध, नियमित और गुणवत्ता आधारित सफाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए. महापौर ने कहा कि स्वच्छ वातावरण जनता का अधिकार है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा. चेतावनी दी गई कि किसी भी स्तर पर कोताही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

नियमित सफाई और देखरेख से स्थानीय लोगों को राहत

महापौर ने ड्रेनों की नियमित निगरानी और वैज्ञानिक तरीके से सिल्ट एवं कचरा निष्कासन को जलभराव से बचाव का प्रभावी उपाय बताया. उन्होंने सफाई व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने और तय मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए. साथ ही अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और सभी नालों को पूरी तरह साफ रखने को कहा. इस मौके पर विधायक अजय महावर ने कहा कि गोकलपुर क्षेत्र में जलभराव और सफाई की समस्या लंबे समय से स्थानीय निवासियों की बड़ी चिंता रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम और प्रशासन की सक्रियता से क्षेत्रवासियों को जल्द राहत मिलेगी और समस्याओं का स्थायी समाधान संभव होगा. दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह के निरीक्षण, समीक्षा और सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेंगी. निगम का उद्देश्य जलभराव की समस्या को पूरी तरह नियंत्रित करना है.

धूल-मलबा-कचरा जलाने वालों पर शिकंजा, दिल्ली सरकार ने जिला समितियां को दिए सख्ती के निर्देश

नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले अक्टूबर में सरकार द्वारा बनाई गई जिला समितियों को और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन समितियों की सह-अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम के उपायुक्त करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विभाग इन समितियों के सदस्य हैं। सरकार ने इन समितियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। विपक्ष इस संबंध में कई आरोप लगा रहा है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, यह दावा करते हुए कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर कचरा जलाया जा रहा है, निर्माण कार्य जारी है, और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई केवल कागजों पर हो रही है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जिला स्तर पर प्रदूषण निगरानी के लिए गठित समितियों को और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इन समितियों का गठन पहली बार पिछले अक्टूबर में किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम क्षेत्र के उपायुक्त सह-अध्यक्ष थे, और प्रदूषण निगरानी और कार्रवाई से संबंधित विभिन्न विभाग सदस्य थे। हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि समितियां सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही थीं। इसके बाद, सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो सरकार की बार-बार की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर मलबा फेंका जा रहा है, जिससे धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद से भी धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर लगातार पानी छिड़कने को कहा गया है। सरकार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बनी प्रदूषण की स्थिति में सुधार करना चाहती है।

GD गोयनका ला-पेटीट, पीतमपुरा द्वारा 'ज़ाइलोपिया 2025-26-उड़ान -ब्रेकिंग बाउंड्रीज' वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया

नई दिल्ली , (अजय कुमार चौधरी) एयरफोर्स ऑडिटोरियम में दिल्ली के अग्रणी प्री-स्कूलों में शुमार GD गोयनका ला-पेटीट, पीतमपुरा ने अपने वार्षिक दिवस समारोह 'ज़ाइलोपिया 2025-26- उड़ान - ब्रेकिंग बाउंड्रीज' का भव्य किया गया। वर्ष 2012 में स्थापित यह संस्थान पिछले 14 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। कार्यक्रम में लगभग 200 बच्चों ने अद्भुत उत्साह, आत्मविश्वास और जोश के साथ भाग लिया, जबकि 600 से अधिक दर्शक बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यालय का संचालन दूरदर्शी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स - कमल कुमार गुप्ता, पी.आर. गुप्ता, योगेश गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। विद्यालय की प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली हेड हेडमिस्ट्रेस दीपिका आर्य के नेतृत्व में स्कूल बच्चों को एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध वातावरण प्रदान कर रहा है, जहाँ नन्हे बच्चे आत्मविश्वास के साथ सीखते और बढ़ते हैं। इस भव्य आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि शिखा भट्ट और डॉ. संगीता भाटिया उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों ने बच्चों की ऊर्जा, अनुशासन और सटीकता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में भारती रखेजा और ललिता मेहता शामिल रहीं। 'ज़ाइलोपिया 2025-26' महिलाओं की शक्ति और उपलब्धियों को समर्पित एक प्रेरणादायक प्रस्तुति रही, जिसमें कल्पना चावला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय महिला क्रिकेट टीम सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिला दिग्गजों को समर्पित किया गया। रंग-बिरंगी पोशाकों, आकर्षक मेकअप और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने यह साबित कर दिया कि लष्ठ गोयनका ला-पेटीट बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और आत्मविश्वास को सशक्त रूप से आकार दे रहा है। यह वार्षिक उत्सव न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर 'उड़ान' का सशक्त प्रतीक भी रहा। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय की समर्पित एडमिन टीम - शिखा अरोड़ा, अनु सेठी, राधना शुक्ला, अनन्या कुकरेजा, कृतिका दुग्गल एवं लवीना का विशेष योगदान रहा। विद्यालय की असली ताकत इसकी 30 शिक्षकों और 35 सपोर्ट स्टाफ की मेहनती टीम है, जिनकी लगन हर प्रस्तुति में साफ झलक रही थी।

संसद बनी मज़ाक!

परंजॉय गुहा ठाकुरता

18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। इस सत्र को उसकी चर्चाओं के लिए नहीं, बल्कि स्थापित नियमों को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने के लिए याद किया जाएगा। सिर्फ 19 दिनों में, संसद कानून बनाने वालों की चर्चा करने वाली सभा से बदलकर केवल औपचारिक प्रक्रियाओं को मंजूरी देने वाली इकाई बनकर रह गई। यह सत्र विवादित कानूनों को जबरदस्ती पास कराने और नेतृत्व की स्पष्ट कमी के लिए जाना जाएगा। इसने संसद को एक तरह से मज़ाक बना कर रख दिया। माहौल चिंताजनक था। जब देश की राजधानी के लोग गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे थे, एक ऐसा संकट जिस पर विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्तावों के ज़रिए चर्चा करने की नाकाम कोशिश की, वहीं संसद के दोनों सदनों के अंदर का माहौल एक ऐसे विधायी एजेंडे से घुटन भरा था, जिसमें जांच-पड़ताल के बजाय जल्दबाज़ी को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार ने दो बड़े बदलाव लाने वाले विधेयकों को कानून बनाने के लिए पास करवाया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, जिसमें हंगामे और अफरा-तफरी के बीच विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए ध्वनि मत का इस्तेमाल किया गया। ध्वनि मत एक ऐसा तरीका है जो अव्यवस्था के बीच, वोटों के रिकॉर्डेड बंटवारे को रोककर, सांसदों को व्यक्तिगत जवाबदेही से प्रभावी ढंग से बचाता है। सरकार ने 12 घंटे से भी कम समय का नोटिस देकर सप्लीमेंट्री लिस्ट के ज़रिए दो बिल पेश करने के लिए अचानक हमला करने वाली रणनीति अपनाई। ज़ोरदार मांगों के बावजूद, सरकार ने इन महत्वपूर्ण विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटियों को भेजने से इनकार कर दिया, जिससे उन कानूनों पर बहस और डिटेल में जांच को नज़रअंदाज़ किया जा सके जो भारत के ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को मौलिक रूप से बदलते हैं और देश के न्यूक्लियर लायबिलिटी सिस्टम को बदलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की जगह लेने वाला (VB-G RAM G) बिल क़ानूनी ढांचे को इस योजना को अधिकार से बदलकर मिशन बनाता है। यह फसल कटाई के मौसम के दौरान एक विवादास्पद 60 दिन का कृषि विराम (कृषि कार्यों का अस्थायी ठहराव) शुरू करता है, जो प्रभावी रूप से कृषि श्रमिकों की मोलभाव करने की शक्ति को खत्म करके उन्हें बंधुआ मज़दूर बना देता है। इसके अलावा, नया बिल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 फंडिंग बंटवारे को अनिवार्य करता है, जिससे रोज़गार गारंटी योजना की व्यवहार्यता को खतरा होता है, खासकर गरीब राज्यों में। महात्मा गांधी का नाम हटाकर RAM संक्षिप्त नाम रखने से विवाद हुआ और सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं। विपक्षी सांसदों ने बिल के हिंदी शॉर्ट फॉर्म में राम का नाम शामिल करने को एक सेक्युलर वेलफेयर प्रोग्राम को सांप्रदायिक बनाने की जानबूझकर की गई कोशिश माना। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आलोचकों को खारिज करते हुए कहा कि गांधी का नाम ओरिजिनल 2005 एक्ट में नहीं था, बल्कि 2009 में बाद में जोड़ा गया था। जहां तक SHANTI बिल की बात है, यह प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की अनुमति देने के लिए 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बदलाव करता है। सबसे ज़्यादा विवादित बात यह है कि यह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाए गए सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज़ को कमज़ोर करता है, जिसे आलोचक एक रेडियोएक्टिव जुआ कहते हैं जो मुनाफे का प्राइवेटाइज़ेशन करता है यानी लाभ निजी हाथों में चला जाता है जबकि जोखिम समाज पर थोप दिए जाते है। यह तर्क दिया गया कि नया बिल अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के कारण पेश किया गया था। यह बिल प्राइवेट ऑपरेटर्स को सूचना का अधिकार एक्ट से छूट देता है, जिससे न्यूक्लियर सुरक्षा के चारों ओर एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। SHANTI बिल का सबसे विवादित पहलू 2010 के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव है, जिसे ज़ोरदार बहस के बाद पास किया गया था और इसमें एक सख्त सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज़ (सेक्शन 17(b)) शामिल था, जो ऑपरेटर को खराब इक्विपमेंट से हुए एक्सीडेंट की स्थिति में सप्लायर पर मुकदमा करने की इजाज़त देता था। यह भोपाल गैस त्रासदी से मिला एक सीधा सबक था। SHANTI बिल इस मुआवज़े के अधिकार को खत्म कर देता है, या कम से कम बहुत कमज़ोर कर देता है, ताकि वेस्टिंगहाउस और इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस जैसी विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया जा सके, जिन्होंने लायबिलिटी जोखिमों के कारण भारतीय बाज़ार में आने से इनकार कर दिया था। परमाणु आपदा की स्थिति में, विदेशी सप्लायर बिना किसी ज़िम्मेदारी के बच जाएगा और भारतीय टैक्सपेयर को मुआवज़े और सफाई का खर्च उठाना पड़ेगा, जो 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये के बीच एक अपेक्षाकृत मामूली रकम तक सीमित है, जो जापान के फुकुशिमा जैसी आपदा की लागत का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका अनुमान 182 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया था। इन दो मुख्य विधेयकों के अलावा, शीतकालीन सत्र में अन्य महत्वपूर्ण विधायी कदम भी देखे गए, जो प्रक्रिया की मज़ाक को और दिखाते है। संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 पारित किया जो बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है। यह तर्क देते हुए विपक्षी सांसदों ने मांग की कि इसे संसदीय पैनल को भेजा जाए, क्योंकि इससे भारतीय बचत पर विदेशी पूंजी का दबदबा हो जाएगा। हालांकि, इस मांग को खारिज कर दिया गया और बिल पास हो गया, जिससे संसदीय जांच के बिना वित्तीय उदारीकरण का चलन जारी रहा। लोकसभा ने विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 और विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2025 भी पारित किए, जिसमें बड़े सरकारी खर्चों को मंजूरी दी गई। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर पर बिना किसी चर्चा के सत्र समाप्त हो गया। एक कार्यशील लोकतंत्र अपने नेताओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। हालांकि, ये शीतकालीन सत्र देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों द्वारा अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए जाना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे जब संसद में MGNREGA को खत्म करने पर बहस हो रही थी। यह एक ऐसी योजना जिसे उन्होंने फरवरी 2015 में लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की असफलता का प्रतीक बताया था। फिर भी, मोदी सरकार ने उसके बाद इस योजना पर खर्च बढ़ाया - मार्च 2020 में महामारी के बाद देशव्यापी सख्त लॉकडाउन के बाद ग्रामीण गरीबी को कम करने में इसका महत्व विशेष रूप से स्पष्ट हो गया। अगर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति सोची-समझी थी, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति एक रणनीतिक गलती लगती है। जब उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (X) पर बिल को ग्रामीण-विरोधी कहा, तब वह जर्मनी में एक कार फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति का फायदा सत्ता पक्ष ने उठाया और विपक्ष कमजोर पड़ गया क्योंकि उनके सांसद लोकसभा में संघर्ष कर रहे थे। यह एक अजीब दृश्य था, जब लोकतंत्र के मंदिर से दो सबसे अहम व्यक्ति गायब थे, जबकि महत्वपूर्ण कानूनों को रद्द किया जा रहा था और नए कानून बनाए जा रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद, फैसले लेने वाली एक संप्रभु संस्था से घटकर राजनीति का एक गौण मंच बन गई है।

सम्पादकीय...

पंजाब में आप

पंजाब के ग्रामीण जिला परिषदों व पंचायत समितियों के चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को जो प्रचंड विजय मिली है उससे यह संकेत मिलता है कि प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को अपार सफलता मिल सकती है और लोगों में आप की भगवन्त मान सरकार के बारे में कोई सत्ता विरोधी भावना नहीं है। इन चुनावों में हालांकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस दूसरे नम्बर पर रही है मगर वह बहुत पीछे है और एक अन्य विपक्षी पार्टी अकाली दल अपनी खोई ग्रामीण जमीन हथियाने की कोशिश में पसीने-पसीने हो रही है। जहां तक भाजपा का सवाल है तो वह बहुत पीछे चौथे स्थान पर रही जिससे यह पता चलता है कि राज्य में इस पार्टी के प्रभाव में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। वैसे गौर से देखा जाये तो आजादी के बाद से पंजाब में कांग्रेस व अकाली दल प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियां रही है मगर कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय कलेवरों के साथ पंजाब के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है लेकिन यह 21वीं सदी चल रही है और राज्य की राजनीति में आधारभूत परिवर्तन आ चुका है, विशेषकर 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने जिस प्रकार आप पार्टी को अपना तूफानी समर्थन दिया और इसे विधानसभा में तीन चौथाई सीटें दीं उससे पंजाब की राजनीति में युगान्तकारी परिवर्तन आया क्योंकि इससे पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि आप जैसी नई पार्टी पंजाब के लोगों को भरमा सकती है और कांग्रेस समेत अकाली दल व भाजपा की राजनीति ध्वस्त हो सकती है। इसकी वजह यह थी कि आप पार्टी ने पंजाब के लोगों को जो सपने दिखाये उनमें राज्य की जमीनी हकीकत की कड़ुवाहट छिपी हुई थी जिसका प्रदर्शन प्रदेश की पिछली कांग्रेस व अकाली सरकारों के दौरान होता रहा था। पंजाब के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रगतिशील सोच के समझे जाते हैं अतःउन्होंने एक नई पार्टी को मौका देना बेहतर समझा। पंजाब में अब हालत यह हो गई है कि शहरी इलाकों से लेकर गांवों के क्षेत्रों तक में आप पार्टी अपनी लोकप्रियता के शिखर को छू रही है। मगर इन ग्रामीण चुनावों के परिणामों से एक और संकेत मिलता है कि राज्य में अकाली-भाजपा गठजोड़ फिर से सिरे चढ़ सकता है क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में पहले से बेहतर परिणाम दिखाये है। राज्य की कुल 347 जिला परिषदें है जिनमें से 346 पर चुनाव हुआ। इसके साथ ही 2838 पंचायत समितियों पर भी चुनाव हुआ। आप पार्टी को 218 जिला परिषदों में विजय मिली जबकि कांग्रेस को 62 व अकाली दल को 46 पर जीत मिली। इस विजय से ही स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के गांवों में अपनी पकड़ बहुत गहरी बना ली है जबकि अकाली दल अभी बहुत पीछे है और कांग्रेस भी उसके आसपास ही घूम रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकाली दल गांवों की पार्टी मानी जाती थी। यदि ग्रामीण चुनावों में ही इसकी इतनी बुरी हालत है तो आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ करिश्मा करने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस की भी है मगर राजनीति में कभी भी किन्हीं हालात को गारंटीशुदा मान कर नहीं चला जा सकता है अतः विधानसभा चुनावों तक आप पार्टी को अपनी वर्तमान गति को जारी रखना होगा और अपनी लोकप्रियता को गिरने नहीं देना होगा। इन चुनावों की एक विशेषता और थी कि ये बैलेट पेपर के माध्यम से हुए थे। बैलेट पेपर से हुए चुनावों के बारे में विपक्षी दल अब कोई बहाना नहीं बना सकते है और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने का रोना नहीं रो सकते है। जिला परिषद चुनावों में भाजपा को केवल सात में ही जीत मिल पाई। इनमें से भी उन स्थानों पर जहां अपेक्षाकृत शहरीकरण का प्रभाव अधिक समझा जाता है। भाजपा से ज्यादा दस स्थानों पर तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत गये। कुल 2838 पंचायत समितियों में से भी आप पार्टी को 1531 पर विजय मिली जबकि कांग्रेस केवल 612 पर और अकाली दल 445 पर ही जीत दर्ज कर पाये। भाजपा भी 73 पंचायत समितियां जीत गई जबकि बहुजन समाज पार्टी 28 पर और 144 पर निर्दलीय जीते। जिला परिषदों में भी बसपा तीन पर कब्जा जमाने में सफल रही जबकि निर्दलीयों ने दस पर अपना दबदबा कायम किया। इससे यह मालूम होता है कि प्रदेश में बसपा का प्रभाव नगण्य होता जा रहा है और यह नामचारे की ही पार्टी रह गई है। मगर 2022 के चुनावों में आप पार्टी की बहुत तेज लहर थी जिसका आभास सभी चुनाव पर्यवेक्षकों को पहले से ही था। ग्रामीण चुनावों में ऐसी कोई स्पष्ट लहर नहीं देखी जा रही थी मगर यह समझा जा रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई विरोधी जनभावना नहीं है लेकिन अकाली दल के पक्ष में एक तथ्य यह जा रहा है कि यह राज्य के मालवा क्षेत्र में पहले से मजबूत हुई है। पार्टी ने इस क्षेत्र के भटिंडा जिले की 17 जिला परिषदों में से 13 पर अपना झंडा गाड़ा जबकि मुक्तसर में 13 में से सात जिला परिषद जीतीं। इसी प्रकार मनसा में इसने 11 में से चार पर कब्जा किया और फरीदकोट की दस में से पांच पर अपना जोर दिखाया। पंजाब का मालवा इलाका घोर ग्रामीण इलाका माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो सीटें जीती है वे मिलीजुली है। इसी प्रकार भाजपा भी पठानकोट जैसे इलाके में बेहतर स्थिति में रही है। कुल मिलाकर पंजाब के ग्रामीण चुनावों में आम आदमी पार्टी का दबदबा ही रहा है जिससे विपक्षी दलों को अपनी चाल बदलने की जरूरत है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बस एक वर्ष दूर ही है।

राहुल का लंच, कृष्णा के संग

त्रिदीब रमण

भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में कुछ तो बुनियादी फर्क है, भाजपा में अगर किसी नेता को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाती है और वह उसका ठीक से निर्वहन नहीं कर पाता तो उन्हें उसकी असली जगह दिखाने में पार्टी शीर्ष कोई कोताही नहीं बरतता। वहीं, कांग्रेस में तो जैसे शीर्ष के करीबी नेताओं को सौ खून माफ है। स्वयं राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में कभी जिन दूल्हों पर पार्टी टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, बाद में वे राहुल के ही बगलगीर नजर आए, उन्हें और भी महती जिम्मेदारियां बदस्तूर मिलती रहीं। पिछले दिनों एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला राहुल उसी कृष्णा अल्लावरू को लंच कराने अपने साथ अशोक होटल के एक नामी दक्षिण के रेस्त्रां में लेकर गए। राहुल के साथ उनकी कार में सीपीआई माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी थे। सनद रहे कि कृष्णा अल्लावरू का कांग्रेस और राजद में ही इतना विरोध था कि बिहार चुनाव के अधबीच उन्हें दिल्ली बुलाना पड़ा, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इनका घेराव कर इनके खिलाफ नारे लगाए। इन पर टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। माना गया कि राहुल गांधी भी इनसे बेतरह नाराज है, पर राहुल व भट्टाचार्य के साथ अल्लावरू का 'सागर रत्ना' लंच इस बात की गवाही नहीं देता। लंच के बाद राहुल ने माले नेता को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें उनके दफ्तर तक छोड़ने गए। कहते हैं भट्टाचार्य के आग्रह पर राहुल उनके साथ माले के दफ्तर चले गए जहां दोनों नेताओं ने अपना क्वालिटी वक्त गुजारा। वहीं कांग्रेस के कुछ आला नेताओं का सोचना है कि राहुल एक बड़े दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम उन्हें वाम दल के दफ्तर तो नहीं जाना चाहिए था। वहीं पार्टी में ही राहुल के कुछ प्रशंसक नेता यह उनकी विनम्रता और बड़प्पन बता रहे है।

पीके से क्यों मिली प्रियंका?

प्रियंका गांधी राहुल से अलहदा कांग्रेस में एक नई किस्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है, शायद यही वजह है कि संसद भवन में स्पीकर की चाय पर उन्हें पीएम व राजनाथ के साथ भी हंसते-बतियाते देखा गया और जब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में उगने वाली नीली हल्दी को दिल्ली के इस दमघोंटू प्रदूषण का तोड़ बताया तो स्वयं पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब लौट कर आते है प्रशांत किशोर पर जिन्होंने एक दिन अचानक प्रियंका के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जिसका लब्बोलुआब यह था कि 'हम हारे या जीते, पर असली सवाल यह है कि इस देश में चुनाव लड़ना अन्य पार्टियों के लिए इतना 'मुश्किल क्यों हुआ जा रहा है?'

प्रियंका को पीके की बात में दम लगा और उन्होंने उन्हें अपने घर मिलने को बुला लिया। कहते हैं यह मीटिंग कोई डेढ़ घंटे चली। सूत्रों का कहना है कि पीके ने प्रियंका से कहा कि 2029 के संसदीय चुनाव से पहले विपक्ष को एक साझा रणनीति बनानी होगी। तभी हम मौजूदा चुनावी प्रक्रिया के समक्ष कोई चुनौती रख पाएंगे। पीके ने कहा कि अगर प्रियंका चाहें तो वे इस बारे में ममता बनर्जी और स्टालिन से बात कर उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला सकते है। पीके ने यह भी कहा कि मौजूदा तंत्र विपक्ष को एक-दो राज्यों में जीतने की छूट दे सकता है ताकि यह भ्रम बना रहे कि देश में लोकतंत्र जिंदा है पर किसी 'की-स्टेट' में विपक्षी पार्टियों का जीत पाना खासा मुश्किल है। कहते हैं पीके ने प्रियंका से यह भी कहा कि बिहार में उन्हें तेजस्वी का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि वे अश्वमेध के असली घोड़े नहीं है। इस पर प्रियंका ने धीरे से कहा यह फैसला तो भाई (राहुल) को ही लेना है।

कैसे लगा यूपी में पंकज का नंबर

भाजपा ने जब केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया तो इसे एक बड़ा सियासी दांव माना गया। कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले पंकज चौधरी सात बार के सांसद हैं। वैसे भी पूर्वांचल और मध्य यूपी में कुर्मी समाज चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आमतौर पर यूपी में कुर्मी वोटरों का लगाव भाजपा से रहा है, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यह वोटर पलट कर सपा के पाले में चले गए थे। आप मान सकते है कि पंकज चौधरी के ऊपर यह पहली महती जिम्मेदारी होगी कि वे अपने सजातीय वोटरों की भाजपा में घर वापसी करवाएं। वैसे तो महाराजगंज संसदीय सीट अब तक भाजपा का अभेद किला रही है, पर 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां की फरेंदा विधानसभा सीट पर अनायास ही कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी जीत गए थे। सनद रहे कि उस चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में बस दो ही विधानसभा सीट जीत पाई थी, इसमें फरेंदा के अलावा रामपुर खास की सीट मोना उर्फ आराधना मिश्रा ने जीती है, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री है। खैर, किसी प्रकार वीरेंद्र चौधरी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आ गए। योगी को उनमें कूवत दिखी कि ये पंकज चौधरी की काट हो सकते है। योगी उन्हें भाजपा में लाने में सक्रिय हो गए, वैसे भी कांग्रेस के यहां मात्र दो ही विधायक थे सो, दलबदल कानून का भी कोई खौफ नहीं था। कहते है योगी ने वीरेंद्र चौधरी से वादा किया कि अगली बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा का टिकट दिया जाएगा। योगी से मिले आश्वासन के बाद वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज में घूमने लगे, लोगों से मेल-जोल बढ़ाने भी लगे, लेकिन तब तक यह खबर पंकज चौधरी को लग चुकी थी। उन्हें 24 में चुनाव भी लड़वाया गया और जीतने पर केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, और हैरत की बात देखिए 24 के चुनाव में उनकी टक्कर भी कांग्रेस के उसी वीरेंद्र चौधरी से हुई जिन्हें योगी भाजपा के टिकट पर लड़वाना चाहते थे। पंकज चौधरी इस चुनाव में वीरेंद्र चौधरी से मात्र 35,451 वोटों के अंतर से ही जीत पाए, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार को सपा का समर्थन हासिल था और कुर्मी वोटरों का ज्यादा झुकाव भी सपा की ओर देखा गया। पंकज चौधरी 'राहत रूह' तेल कंपनी के मालिक भी है, जिनके बारे में उनके प्रतिद्वंद्वी वीरेंद्र चौधरी ने एक कार्यक्रम में कह दिया था- 'आप तो कुबेर के खजाने के मालिक है।' क्या अब इस खजाने की चाभी से योगी को 'डिकोड' किया जा सकेगा? यही महती जिम्मेदारी तो पंकज चौधरी को सौंपी गई है।

यदि सेवानिवृत्ति से पहले निर्णय लेने की यह प्रवृत्ति अनियंत्रित रही, संवैधानिक संस्थाओं के लिए आत्मचिंतन का आह्वान है

वैश्विक स्तरपर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता का प्रयोग समय,नियम और उत्तरदायित्व से बंधा होता है। चाहे वह कार्यपालिका हो, न्यायपालिका या विधायिका, हर संस्था का उद्देश्य जनहित में निष्पक्ष, संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। किंतु वर्षों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या कार्यकाल समाप्त होने से कुछ समय पूर्व असामान्य रूप से बड़ी संख्या में आदेश, निर्णय और नीतिगत फैसले पारित करना। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व की अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस पर गंभीर बहस चल रही है।भारत में यह चलन अब केवल प्रशासनिक अनुभव या लोककथाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था ने स्वयं इसपर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है।यह स्थिति न केवल संस्थागत नैतिकता पर प्रश्न उठाती है, बल्कि निर्णयों की वैधता,निष्पक्षता और दीर्घकालिक प्रभाव पर भी गहरा संदेह पैदा करती है।कार्यपालिका में रिटायरमेंट सिंड्रोम-प्रशासनिक फैसलों की अचानक बाढ़भारत की कार्यपालिका संरचना,ग्राम स्तर के पटवारी कार्यालय से लेकर मंत्रालय स्तर तक,एक जटिल नौकरशाही तंत्र पर आधारित है। इस तंत्र में वर्षों तक अनेक फाइलें, प्रस्ताव और निर्णय लंबित रहते हैं। किंतु यह अक्सर देखा जाता है कि किसी अधिकारी के रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में वही फाइलें असाधारण गति से निपटाई जाने लगती है, जिन पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या पहले निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी? क्या अब निर्णय लेने के पीछे किसी प्रकार का दबाव, भ्रष्टाचार,हित या जल्दबाजी है ? या फिर यह मान लिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद जवाबदेही सीमित हो जाएगी? या फिर अपने रिटायरमेंट की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए हर पैसे का अधिक से अधिक अरेंजमेंट इसका सबसे बड़ा कारण है? प्रशासनिक नैतिकता के वैश्विक सिद्धांतों के अनुसार,निर्णय की गुणवत्ता समय से स्वतंत्र होनी चाहिए, न कि सेवा समाप्ति की तारीख से प्रेरित। साथियों बात अगर हम पटवारी से मंत्रालय तक अंतिम दिनों की स्पीड गवर्नेंस की खासकर ग्राम स्तरपर भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, पट्टा वितरण जैसे मामलों में पटवारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि ऐसे मामलों में रिटायरमेंट के ठीक पहले तेजी से निर्णय लिए जाएं, तो उसके सामाजिक और कानूनी प्रभाव दशकों तक बने रहते हैं।यही स्थिति जिलास्तर, राज्य सचिवालय और केंद्रीय मंत्रालयों में भी देखी जाती है।अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक अध्ययन बताते है कि लास्ट-मिनट डिसीजन मेकिंग भ्रष्टाचार, पक्षपात और भविष्य के विवादों की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए विकसित देशों में अक्सर सेवा समाप्ति से कुछ समय पूर्व निर्णय लेने की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है या उन्हें सामूहिक समीक्षा के अधीन रखा जाता है।

साथियों बात अगर कर हम न्यायपालिका में बढ़ती प्रवृत्ति न्याय का अंतिम ओवर इसको समझने की करें तो न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे नैतिक और निष्पक्ष स्तंभ माना जाता है। न्यायाधीशों के निर्णय केवल कानूनी विवाद नहीं सुलझाते, बल्कि समाज के लिए नैतिक दिशा भी तय करते हैं।ऐसे में यदि न्यायपालिका में भी रिटायरमेंट से ठीक पहले असामान्य संख्या में फैसले सुनाने की प्रवृत्ति बढ़े, तो यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि कुछ न्यायाधीश क्रिकेट मैच के अंतिम ओवर में छक्के मारने की तरह फैसले सुना रहे है। यह टिप्पणी केवल एक रूपक नहीं, बल्कि एक गहरी संवैधानिक चेतावनी है।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी-न्यायिक आत्ममंथन का क्षण, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट असहमति व्यक्त की। मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई,जिन्हें सेवानिवृत्ति से मात्र 10 दिन पूर्व निलंबित कर दिया गया थापीठ ने कहा कि कुछ न्यायाधीशों में रिटायरमेंट से पहले बहुत अधिक आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है,जो न्यायिक प्रणाली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की जल्दबाजी न्याय की गुणवत्ता और संस्थागत विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।सुप्रीम कोर्ट का रुख-अनुशासन बनाम सहानुभूति, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिका पर सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायाधीश को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।यह निर्णय अपने आप में एक संदेश है कि संस्थागत अनुशासन व्यक्तिगत परिस्थितियों से ऊपर है। न्यायपालिका का आत्मनियमन लोकतंत्र के लिए उतना ही आवश्यक है,जितनाकार्यपालिका या विधायिका का।यह रुख यह भी दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अब केवल बाहरी संस्थाओं की निगरानी नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं अपनी प्रणाली की कमजोरियों को पहचानकर सुधार की दिशा में कदम उठा रहा है। साथियों बात अगर हम विधायिका में अंतिम क्षणों के कानून,वैश्विक अनुभव इसको समझने की करें तो,यह प्रवृत्ति केवल न्यायपालिका या कार्यपालिका तक सीमित नहीं है।

विधायिका में भी अक्सर देखा जाता है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सरकारें तेजी सेअध्यादेश संशोधन और विधेयक पारित कराती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लैम- डक लेजिस्लेशन कहा जाता है,जिसे अमेरिका यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है।ऐसे कानून अक्सर पर्याप्त बहस, संसदीय समीक्षा और सार्वजनिक विमर्श के बिना पारित होते हैं, जिससे बाद में संवैधानिक विवाद और सामाजिक असंतोष पैदा होता है। साथियों बात अगर हम संवैधानिक नैतिकता और संस्थागत विश्वसनीयता का प्रश्न को समझने की करें तो भारतीय संविधान केवल शक्तियों का वितरण नहीं करता, बल्कि संवैधानिक नैतिकता की भी अपेक्षा करता है।

कब तक घरों में कैद रहेगा 'बचपन'

कहते हैं मुसीबत जब आती है अकेली नहीं आती वह अपने साथ कई और चुनौतियां भी लाती है। बढ़ते प्रदूषण ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, यह बात हर कोई जानता है लेकिन हमें आपदा अर्थात बुरे वक्त से लड़ने का जज्बा खुद ही तैयार करना होगा। यह इसलिए जरूरी है कि हमें जो कुछ करना है वह नौनिहाल अर्थात नन्हे-मुन्ने बच्चों को जहरीली हवा से बचाने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की खातिर है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से एक बड़ा सवाल यह है कि नन्हे-मुन्ने बच्चों का मानसिक विकास करना कितना जरूरी है। कोई भी आपदा यह मुसीबत बच्चों के स्वच्छंद विचारों और उनकी सुन्दर सोच पर असर न कर सके। पिछले दिनों मुझे डिबेट के दौरान यह बात दिल तक छू गई जब मुझसे सवाल किया गया कि आखिरकार हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे कब तक घरों में कैद रहेंगे। कोरोना के दौरान क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान हर कोई घरों में कैद होकर रह गया था। बड़ों को हालात देखकर समझना आता है लेकिन जो नन्हे-मुन्ने बच्चे गोदी में खेल रहे हैं या जिनकी उम्र महज पांच-छह या दस साल तक की है, वे बहुत मासूम होते हैं। उन्हें हम यह कहें कि पाल्यूशन की वजह से आप घर पर ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का मासूम सवाल दिल को हिला कर रख देता है जब वे पूछते हैं- पाल्यूशन क्या होता है। जरा सोचिए हम बच्चों को अच्छा हृष्ट-पुष्ट बनाने और अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए ताजी हवा में सैर करने और कसरत करने की बात करते है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हवा में जहर घुलता जा रहा है तो सीधी सी बात है कि बच्चे के मन-मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है कि बच्चों को जीवन में खुला और मुक्त वातावरण चाहिए। उन पर किसी किस्म की बंदिश यह रोक-टोक नहीं होनी चाहिए लेकिन जब हम उन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे तो फिर उनका मानसिक विकास कैसे होगा? मेरा मानना है कि हालात के मुताबिक हमें बच्चों को प्रदूषण से लड़ने के लिए उनका मानसिक विकास कराना ही होगा। घर के अन्दर बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि वे कैद कर दिए गए है। यह सोच नकारात्मक असर डाल सकती है। अगर घर के अन्दर खेलों की गतिविधियां चाहे वे टेबल टैनिस, अन्य हल्का रस्साकूद जैसी खेलें हों तो उन्हें बिगड़ते और प्रदूषण जैसे हालात से लड़ने में मानसिक रूप से ताकत मिल सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को किस तरह हालात से लड़ना सिखा रहे है। एक अमरीकी रिपोर्ट बताती है कि भारत में कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों के बच्चे गर्मी-सर्दी के बीच और कोरोना तथा पाल्यूशन जैसी समस्याओं के चलते ज्यादा मजबूत रहते हैं और वे इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। जब बच्चों पर बंदिशें लगाकर उन्हें घर पर ही टीवी और मोबाइल देकर छोड़ दिया जाएगा तो फिर वे हालात से नहीं लड़ पाएंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

खेल मंत्री मांडविया ने किया 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ के समारोह का नेतृत्व

नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को यहां 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल की पहली वर्षगांठ के समारोह का नेतृत्व किया जिसमें 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और यहां रॉक बीच पर साइकिल चलाई। भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश और टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल भी इस साइकिल रैली का हिस्सा बने। इस रैली में स्कूली बच्चों, नमो साइक्लिंग क्लब के सदस्यों और पुडुचेरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया। खेल मंत्रालय के अनुसार, 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल पिछले एक साल में देश भर के 700 से अधिक जिलों में दो लाख स्थानों पर आयोजित की गई जिसमें वर्ष भर में 20 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मांडविया ने कहा, ''जब हमने एक साल पहले इस पहल की शुरुआत की थी तब इसका आयोजन केवल पांच स्थानों पर लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ किया जाता था लेकिन अब प्रत्येक रविवार को देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन होता है जिसमें 10 लाख से अधिक नागरिक

नियमित रूप से भाग लेते हैं। यहां आयोजित समारोह में जुम्बा, कैरम, शतरंज, मल्लखंब, सिलंबम, योग, रस्सी कूद जैसी गतिविधियां भी शामिल थी। देश के 10,000 से अधिक स्थानों पर रविवार को इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन स्थानों में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) और खेलो इंडिया केंद्र, हजारीबाग, कारगिल, पटियाला, लखनऊ, गोलाघाट, राजनांदगांव, हिसार, तिनसुकिया, विशाखापत्तनम, काशीपुर, कटक आदि शामिल हैं। मांडविया ने कहा, ''अब से प्रत्येक महीने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साइकिल चालकों पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप से नजर रखी जाएगी और शीर्ष तीन पर रहने वाले चालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम नागरिक को साइकिलिंग को दैनिक आदत के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पुरस्कृत करना है। इस अवसर पर श्रीजेश ने कहा, ''फिट रहना पदक जीतने के लिए प्रशिक्षण लेने तक सीमित नहीं है बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में अनुशासन और संतुलन बनाने से भी जुड़ा है। साइकिल चलाना एक आदत है लेकिन जब इसे सामूहिक रूप से अपनाया जाता है तो यह एक स्वस्थ समाज और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय खेल मंत्री की 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल ने फिटनेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया है।

सीएम के पूर्व ओएसडी का किया स्वागत

मुरादाबाद। अभिषेक कौशिक (पूर्व ओएसडी, उत्तर प्रदेश शासन; अध्यक्ष, टेनिस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश) के मुरादाबाद आगमन पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मुरादाबाद इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत समारोह जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा के निवास पर आयोजित हुआ। समारोह में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विमलेंद्र शर्मा 'विमल', प्रांतीय उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, महानगर अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, महानगर महामंत्री सुनील शर्मा सहित राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, मनोज शर्मा, दिनेश यादव, अरविंद शर्मा, डॉ. सुनील शर्मा, विशाल गुप्ता, संदीप कौशिक, नीरज शर्मा, विपिन शर्मा, कार्तिक शर्मा, अमित शर्मा, राजू, रजत शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री अभिषेक कौशिक ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए देश व समाज हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए संगठनात्मक एकता, पारिवारिक समन्वय तथा समाज के प्रति सकारात्मक भूमिका निभाने पर विशेष बल दिया।

पं. रामप्रसाद बिस्मिल महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से बने थे क्रांतिकारी

मुरादाबाद।

आर्य समाज स्टेशन रोड पर काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस मनाया गया। पं वीरेंद्र आर्य ने मथुरा प्रसाद आर्य की यज्ञमानी में वैदिक रीति से यज्ञ संपन्न कराया तत्पश्चात मथुरा से आमंत्रित भजनोपदेशक आचार्य उदयवीर आर्य ने काकोरी के क्रांतिकारियों की बलिदानी गौरवगाथा को गीतों के द्वारा सुनाकर वातावरण देशभक्ति भावना से ओत-प्रोत कर दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता मेजर डा राजीव ढल ने बताया कि पं. रामप्रसाद बिस्मिल महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी पूर्णानन्द से प्रेरित होकर देश की आजादी की क्रांति सम्मिलित हुए। बिस्मिल ने आर्य समाज शहाजहांपुर को अपनी मां मानते हुए अपना घर छोड़ दिया और वहीं क्रांतिकारियों की शरणास्थली बन गया। अशफाक उल्ला खां हसरत वारसी ने भी अपना घर त्याग कर बिस्मिल के साथ आर्य समाज में

ही रहकर क्रान्तिकारी योजनाएं बनाते रहे। रामप्रसाद बिस्मिल आदि क्रांतिकारी आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद स्थित शहीद भवन में भी आकर ठहरते और योजना बनाते थे। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का बहुत प्रभाव क्रांतिकारियों के जीवन पर पड़ा। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई जो बहुत ही विश्वनीय योजना का रुप था लेकिन अपने भेदियों के कारण ही सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गये । इस पर वक्ता ने किसी कवि की रचना पढ़ी - जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वहीं अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। क्रांतिकारी देश को आजाद कराने मे अपने प्राणों को बलिदान कर गये । 19दिसम्बर 1927 का दिन भारत की आजादी की क्रांति का बलिदानी दिवस है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वारा देश के अनेकों नौजवानों को देश की क्रांति की ओर प्रेरित किया। मुख्य वक्ता ने रामप्रसाद बिस्मिल के प्रिय गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,देखना है ज़ोर कितना बाजुएं कातिल में है, को सुनाकर अपनों उद्बोधन सम्पन्न किया। अंत में 14 दिसम्बर को महानगर के विद्यालयों के बच्चों की भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रधान डा. अभय श्रोत्रिय,डा राम मुनि,मंत्री रमेश सिंह आर्य एडवोकेट, ज्ञानेंद्र गांधी धवल दीक्षित बिजेंद्र सिंह यादव, आलोक कुमार, लोकेश आर्य यशपाल आर्य, मयंक आर्य विजय कौशिक सुमित आर्य मौरा सोती शत्रो गुप्ता गायत्री आर्य ऊषा गुप्ता, अरबिंद आर्यबंधु निर्मल आर्य राकेश कुमार राजेश नारंग उमेश आर्य ज्ञान प्रकाश रस्तोगी, विजय नन्दन, हरवीर सिंह वेद मुनि रामाशंकर आर्य मनोज योगगुरु शिवम् आर्य, संतीश मदान, जितेंद्र आर्य उत्तम सिंह आर्य आदि उपस्थित रहे।

जीआईसी में आयोजित हुआ पुरातन छात्रों का सम्मेलन

मुरादाबाद। महानगर के जीआईसी में भव्य पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 66 बैच से लेकर 1991 बैच तक के पुरा छात्र उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्र'ज्वलित करके किया गया। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। पुरा छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समां बांधा।

इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ अशोक कुमार, डॉ अमित रस्तोगी, .डा पीएन टण्डन, डा. जेपी टण्डन, डा संजय शाह, डा. पुष्पेंद्र कुमार, डॉ अनुराग दूबे, डा डी के गुजरती, डा आर सी अग्रवाल, डॉ सत्य प्रकाश, डॉ ए के वर्मा, डा. अखिल अग्रवाल, डा विनोद पुरी उपस्थित रहे। शहर के प्रतिष्ठित नियोंतक श्री अवधेश अग्रवाल सुनील भंडुला, योगेश चंदकोठीवाल उपस्थित रहे। अखिल

कुमार शुक्ला रिटायर्ड डी.जी.पी त्रिपुरा, विनोद जौहरी, आयुक्त आयकर विभाग की भी उपस्थिति रही।

सी. ए मनोजकुमार, अजीत अग्रवाल तथा कैप्टन विनय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन हेतु एक कोर कमेटी का गठन किया गया था जिसने इस भव्य आयोजन को अन्जाम दिया। इस कोर कमेटी में नियोंतक निर्मल कुमार मेहता, डॉ मनोज अग्रवाल, सजीव गोयल, गोपाल हरि, पंकज गुप्ता तथा विद्यालय स्तर पर डा. विम्मी रस्तोगी थे। स्वागत भाषण राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद के प्रधानाचार्य बलवीर सिंह द्वारा दिया गया। उन्होंने पुरा छात्रों से विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार में सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन डॉ विम्मी रस्तोगी तथा संजीव गोयल ने किया ।

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा सरकार का मकसदः डॉ. आमिर

मुरादाबाद।

युवक कांग्रेस के प्रभारी डॉ. आमिर ने कांग्रेस द्वारा बनाई सरकारी योजनाओं के नाम बदले जाने को लेकर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करना ही जानती है, विकास कार्यों से उसका कोई सरोकार नही है। रविवार को युवक कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान वे किसरौल मोहल्ले में देहात विधानसभा की इकाई की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व सरकार की चोर नीति पर चोट करती रहेगी। डॉ आमिर ने कहा कि मनरेगा समेत सरकारी संस्थाओं के नामो की चोरी हो या वोट चोरी, कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर मौन नहीं रहेगी। इस दौरान युवक कांग्रेस नेत्री शरुती ने भी बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिला

युवक कांग्रेस के प्रभारी ने साधा निशाना

के बुर्का हटाए जाने को भाजपा के महिला विरोधी आचरण का सार्वजनिक प्रमाण बतलाया। अंत मे आभार अभिव्यक्ति असलम खुर्शीद ने की। बैठक में अध्यक्ष अरमान खुर्शीद, पूर्व जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद, वरिष्ठ नेता विवेक गुप्ता, सुधीर पाठक ,अकरम खा, भयंकर सिंह बौद्ध, अफजल साबरी, अरविंद चौहान, मोहतसीम मुख्तार, पार्षद गण जुनैद, मीअज्जम, शमशेर अली, फैसल अंसारी, अकरम, बाबर, समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे।

दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगारी और भूख से परेशान, सरकार से की ये अपील

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी हवा से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो चुका है. हालात दिन पर दिन और भी खराब होते जा रहे हैं. सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कवायदें कर रही है लेकिन वह अब तक कारगर साबित होते नहीं दिख रहे हैं. प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश में सरकार ने ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी है. जिसके लागू होते ही सभी निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं.

जिसका सीधा असर उन हजारों दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी रोज़ी-रोटी ईंट, सीमेंट और कुदाल से चलती थी. दिल्ली के नाकों पर खड़े ये मजदूर आज काम नहीं, सिर्फ़ उम्मीद और मायूसी लेकर लौट रहे हैं. हालांकि, सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए सहायता की घोषणा की है, लेकिन सवाल उन लाखों का है जो सिस्टम से बाहर रह गए हैं. हर तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है. इसका सबसे बड़ा खामियाजा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भुगत रहे हैं. रोज़ कमाकर खाने वाले ये लोग अचानक पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं. न काम है, न आमदनी और न ही भविष्य की कोई स्पष्ट राह दिख रही है.

पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मजदूरों की दुर्दशा

सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है और अधिकारियों द्वारा इस पर अमल भी किया जा रहा है. लेकिन दिल्ली में लाखों की संख्या में ऐसे मजदूर हैं जो पंजीकृत नहीं हैं. इन्हें न तो प्रक्रिया की जानकारी है और न ही कोई मार्गदर्शन मिला. ऐसे में ये मजदूर खुद को पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. जिनसे बात कर उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने लाइव की टीम दिल्ली की विभिन्न चौक-चौराहों पर पहुंची. जहां उनके विषम हालातों में होने का पता चला.

रोजमर्रा की कठिनाइयों और मजदूरों की अपील

एबीपी लाइव की टीम जब वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर, विकासपुरी और पीपल चौक के नाकों पर पहुंच कर मजदूरों से बात की तो मजदूरों ने बताया कि वे पिछले एक महीने से रोज़ सुबह नाके पर आते हैं कि शायद कोई काम मिल जाए.

लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ को रोज ही सबको खाली हाथ लौटना पड़ता है. उम्मीद हर सुबह जन्म लेती है और शाम तक दम तोड़ देती है. उत्तर प्रदेश के महोबा से आए मजदूर स्वरूप और छोटेलाल ने बताया कि वे पिछले पांच साल से दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहे थे. लेकिन पिछले डेढ़ महीने से काम अनियमित हो गया है. बीते एक हफ्ते से तो बिल्कुल काम नहीं मिल रहा. जो पैसे परिवार को भेजने थे, वही अब खुद के खाने में खर्च करने पड़ रहे हैं. हमीरपुर के रहने वाले युवा विक्की ने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा है और मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता. निर्माण कार्य बंद होने से वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया है. खाने के लिए पैसे नहीं हैं. मंदिर, गुरुद्वारे और कभी-कभी लगने वाले लंगर से ही पेट भर पाता है. कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब खाली पेट सिर्फ़ पानी पीकर सोना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के बदायूं से आए विक्की और उसके भाई सहवाग ने बताया कि वे कुछ महीने पहले दिल्ली आए थे. शुरुआत में काम ठीक चल रहा था, लेकिन अब रोज़ सुबह पांच बजे नाके पर आने के बाद घंटों इंतजार और फिर निराश होकर कमरे पर लौटना उनकी दिनचर्या बन गई है.

दसवीं पास होने बावजूद उन्हें कोई और काम नहीं मिल रहा. बिहार के भागलपुर और मोतिहारी से आए राजमिस्त्री संतोष कुमार शाह और तस्लीम ने बताया कि वे पंजीकृत मजदूर थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन दो महीने पहले खत्म हो गया था और वे रिन्युअल नहीं करा पाए. कॉल आने के बावजूद अनपढ़ होने के कारण वे बात समझ नहीं सके. आज हालात बिगड़े तो अपनी इसी चूक का गहरा पछतावा हो रहा है. इन नाकों पर खड़े मजदूर केवल कंस्ट्रक्शन जैसे काम ही कर सकते हैं. मॉल या दुकानों में इन्हें काम मिलना लगभग असंभव है. प्रदूषण के चलते सारे काम बंद हैं. उधार लेने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि उनके साथी मजदूर भी बेरोजगार हैं और सभी खाली हाथ हैं. इन मजदूरों की एक ही मांग है कि सरकार गैर-पंजीकृत मजदूरों के बारे में भी सोचे.

उन्हें नहीं पता कि पंजीकरण कहां और कैसे कराना है. राजधानी दिल्ली में लाखों ऐसे मजदूर हैं जो सिस्टम की जानकारी के अभाव में सहायता से वंचित रह जाते हैं. इनकी अपील है कि सरकार इन्हें भी पंजीकृत मजदूरों की तरह सहायता राशि दे, ताकि कम से कम वे और उनका परिवार भूखे न सोए.

दिल्ली-एनसीआर में त्योहारों से पहले क्लब-पब पर शिकंजा, सैकड़ों को नोटिस और कई सील

नई दिल्ली। गोवा के एक क्लब में हाल ही में हुई आग लगने की घटना के बाद, दिल्ली फायर सर्विस ने राजधानी में नए साल और त्योहारों के मौसम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बढ़ती भीड़ और संभावित जोखिमों को देखते हुए, फायर डिपार्टमेंट ने क्लबों, होटलों, रेस्टोरेंट और पबों में आग से सुरक्षा के इंतजामों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए एक विशेष इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू की है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 से 19 दिसंबर के बीच राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में कुल 97 प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान, यह पाया गया कि 31 क्लब और रेस्टोरेंट आग से सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इनमें से कई जगहों पर, फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था, और कुछ मामलों में, इमरजेंसी एग्जिट रास्ते बंद पाए गए। सभी 31 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जो क्लब और रेस्टोरेंट, जहां गंभीर कमियां पाई गईं, उन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों में आग बुझाने के उपकरण या तो खराब हालत में थे या पूरी तरह से गायब थे। कुछ जगहों पर, इमरजेंसी की स्थिति में भीड़ को कंट्रोल करने और लोगों को निकालने के लिए कोई प्रभावी सिस्टम नहीं था, जिसके कारण यह कड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि, यह देखते हुए कि दिल्ली में अनुमानित तीन हजार से ज्यादा बार और क्लब चल रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गति काफी धीमी मानी जा रही है। इस पर, अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। फायर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह अभियान दिल्ली सरकार के निर्देशों पर शुरू किया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नए साल के जश्न और त्योहारों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। फायर डिपार्टमेंट ने सभी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आग से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अधिकारी के अनुसार, इंस्पेक्शन के दौरान, आग से सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजामों को अच्छी तरह से जांच की जा रही है। इसमें आग बुझाने के उपकरणों की कार्यक्षमता, इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता और पहुंच, बिल्डिंग बायलॉज का पालन और सुरक्षा मानकों की स्थिति शामिल है। जिन प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया था, उनमें आग बुझाने के उपकरणों तक पहुंच और इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता की कमी थी। गाजियाबाद में 7 से 13 दिसंबर तक चलाए गए एक ऑपरेशन में, 125 प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन किया गया।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित समागम का हुआ आयोजन

चंडीगढ़ ।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब गोबिंदपुरा, भम्भौली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज इस पवित्र धरा पर आप सबके बीच में आकर मेरा मन श्रद्धा और गौरव से भर गया है। आज हम यहां उस महान विरासत को नमन करने आए हैं, जिसने न केवल भारत की अस्मिता को बचाया, बल्कि मानवता को धर्म और सत्य के लिए सर्वस्व अर्पण करने का मार्ग दिखाया। आज का यह शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी तथा माता गुजर कौर जी और चारों साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित है। उन्होंने कहा कि समागम में पंथ के महान कीर्ति जत्थे और विद्वान कथा वाचकों द्वारा जो गुरुवाणी का प्रवाह यहां हो रहा है, उससे हमारी साध संगत तो निहाल होगी ही, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी भी गुरु साहिबान और वीर साहिबजादों की शहादत से प्रेरित होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट को 31 लाख रुपये देने की घोषणा की। गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का चित्र व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस समागम में बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह गुरु साहिब की उस शिक्षा का ही विस्तार है, जिसमें कहा गया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने रक्तदान के लिए उमड़े युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। साथ ही, इस समागम के आयोजन के लिए बाबा जसदीप सिंह व आयोजकों का हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरबंसदानी दशम पातशाह श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। केवल 6 और 9 वर्ष की छोटी सी आयु में शहादत देने वाले उनके वीर बेटों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जब भी याद किया जाता है, तो हर किसी की जुबान से निकलता जिंदा वह माका शब्द निकलते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जहां मासूम बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए दीवारों में जिंदा चिनवाना स्वीकार कर लिया लेकिन झुकना स्वीकार न किया हो। उनके परिवार के सभी सदस्यों ने धर्म व आम जन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वह कुर्बानी इतिहास के पन्नों पर सदैव अंकित रहेगी। उन्होंने कहा कि यह शहादत हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती।

माता गुजर कौर जी ने जिस तरह जेल की ठंडी बुर्जियों में रहकर भी अपने पोतों को धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा दी, वह आज की माताओं और बहनों के लिए भी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हर साल 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरबंसदानी श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे उतनी बार ही राष्ट्र हित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए प्रेरित होंगे।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के बच्चों को देश व धर्म के लिए बलिदान देने की दृढ़ भावना विरासत में मिली थी। उनके दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी देश व धर्म के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया था। यह वर्ष उनके बलिदान का 350वां वर्ष है। उनका नाम जुबान पर आते ही हमारे सामने एक ऐसे महापुरुष की छवि उभर कर आती है जिन्होंने धर्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अधिकार और आजादी के साथ भी जोड़ा और कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गुरु साहिबान की शिक्षाओं व सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। पिछले दिनों हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम एक नवंबर हरियाणा दिवस से लेकर गुरु जी के शहीदी दिवस 25 नवंबर तक चले। गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में भाग लेकर गुरु जी को नमन किया। उन्होंने गुरुजी की याद में एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया।

इसके साथ गुरुजी की शिक्षाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है, वह हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी पर शोध के लिए स्थापित की गई वह चेयर शोध परंपरा को नई दिशा देगी। गत 11 नवम्बर को ही, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा है। हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले हरियाणा के 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब गोबिंदपुरा की प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश खपरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी सहित अन्य अधिकारी व साध संगत बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसादा के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप त्याग का दिया संदेश

*यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा

हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके, 3.3 तीव्रता से कांपी धरती

रोहतक। रोहतक जिले में रविवार दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई। भूकंप दोपहर 12 बजकर 13 मिनट 44 सैकंड पर आया। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र रोहतक से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में सांपला और इस्माईला गांव के बीच स्थित बताया गया है। भूकंप का अक्षांश 28.78 और देशांतर 76.73 दर्ज किया गया, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई जा रही है। कम गहराई पर आए भूकंप के कारण झटके आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तीव्रता का भूकंप सामान्य श्रेणी में आता है और इससे बड़े नुकसान की संभावना नहीं होती।

राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है कांग्रेस

अवैध प्रवासियों को असम में बसाना चाहती है- मोदी

असम ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ''राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है और असम में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसाने में मदद कर रही है। असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने यहां पुराने संयंत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वह अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को असम में बसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टी का असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव से कोई लेना-देना नहीं है, जिसे भाजपा ने बचाने की कोशिश की है।

मोदी ने कहा, कांग्रेस मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है क्योंकि वह केवल सत्ता हथियाना चाहती है। वह मेरे अच्छे कार्यों का विरोध करती है भाजपा सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, भूमि, गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करती रहेगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य असम को उतना शक्तिशाली बनाना है जितना कि वह अंग्रेम साम्राज्य के समय हुआ करता था। मोदी ने कहा, ''औद्योगीकीकरण और कनेक्टिविटी असम के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाजपा की 'डबल-इंजन सरकार युवाओं को नए सपने देखने के लिए सशक्त बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत तभी प्रगति कर पाएगा जब किसान समृद्ध होंगे, और भाजपा सरकार ने उनके विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है। मोदी ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान कई उर्वरक कारखाने बंद हो गए थे। जब हम सत्ता में आए, तो भाजपा सरकार ने पूरे देश में कई नए संयंत्र स्थापित किए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पाम ऑयल मिशन से पूर्वोत्तर को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में किसानों की आय बढ़ेगी।

डिब्रूगढ़ में यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया

बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए उन्हें बचा भी रही, इसलिए एसआईआर का विरोध- पीएम मोदी

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर : पुलिस-एसटीएफ की गोली से दो बदमाश ढेर

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश में रविवार की सुबह पुलिस और एसटीएफ ने आतंक का पर्याय बने दो बदमाशों का शिकार किया। एसटीएफ ने एक लाख के इनामी सिराज अहमद को मार गिराया, तो पुलिस ने 50 हजार के इनामी आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर के ढेर कर दिया। लोगों को परेशान करना, उनमें दहशत फैलाना इन बदमाशों का मुख्य पेशा बन गया था। पहला एनकाउंटर बुलंदशहर में हुआ। यहां पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर को मार गया। जबकि, इसका साथी भागने में सफल रहा। हालांकि इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए बदमाश पर विभिन्न जिलों में हत्या और लूट जैसे 47 गंभीर मामले दर्ज थे। यह मेरठ जिले के श्यामनगर क्षेत्र के लिसाड़ी गेट का रहने वाला था। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मारा गया बदमाश जुबैर उर्फ पीटर शातिर अपराधी था। 2 नवंबर 2025 को कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई एक लूट की घटना में यह वांछित चल रहा था। इस पर 50 हजार का इनाम घोषित था। इसका एक साथी फरार हो गया है।

उसकी तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बुलंदशहर में बदमाश के ढेर होने के कुछ देर बाद ही एसटीएफ ने यहां से करीब 200 किमी दूर सहारनपुर में एक लाख के इनामी बदमाश सिराज अहमद को मार गिराया। यह सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के लोलेपुर गांव का रहने वाला था। बताते चलें कि 6 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने जिले में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस जांच में हत्या का मुख्य आरोपी के रूप में सिराज अहमद का नाम सामने आया था। इसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी।

लेकिन, वह फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया था। लगातार दबिश के बावजूद वह पुलिस की पकड़ से बाहर था। फरारी के दौरान मार्च 2025 में न्यायालय के आदेश पर सुरक्षा मानकों की स्थिति शामिल है। जिन प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया था, उनमें आग बुझाने के उपकरणों तक पहुंच और इमरजेंसी एग्जिट की उपलब्धता की कमी थी। गाजियाबाद में 7 से 13 दिसंबर तक चलाए गए एक ऑपरेशन में, 125 प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन किया गया।

पीड़ित परिवार ने बांटी मिठाई; योगी का जताया आभार

उसकी करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इसके बाद भी वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। सिराज के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली तो अधिवक्ता आजाद अहमद के घरवालों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मिठाई बांटी और इस न्याय के लिए सीएम योगी का आभार जताया। मृतक अधिवक्ता के पिता मो. सलीम और भाई मुनव्वर ने कहा कि सीएम पर हमें भरोसा था, कि न्याय मिलेगा। आज हमें न्याय मिल गया। पुलिस के अनुसार, सिराज अहमद का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हत्या, हत्या के प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका जैसी गंभीर धाराओं में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं।

पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर मढ़ रहे दोष

नई दिल्ली।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। खरगे ने कहा कि केंद्र और असम दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, जिसे वे खुद डबल इंजन सरकार कहते हैं। ऐसे में यदि सुरक्षा व्यवस्था में विफलता है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर कैसे डाली जा सकती है? दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वह अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को असम में बसाने की कोशिश कर रही है।

वे देशद्रोही हैं, हम नहीं- खरगे

असम दौरे पर पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, केंद्र में उनकी सरकार है और असम में भी उनकी सरकार है, जिसे वे डबल-इंजन सरकार कहते हैं। अगर वे सुरक्षा देने में असफल हो जाते हैं, तो वे विपक्षी पार्टियों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहती है, तो सारा दोष विपक्ष पर मढ़ देती है। मैं ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। खरगे ने आगे कहा, वे राष्ट्रविरोधी हैं, हम नहीं। हम देश के हित में जो भी अच्छा होगा, वह करेंगे, लेकिन हम आतंकवादियों, घुसपैठियों या किसी और का समर्थन नहीं करेंगे। वह सिर्फ दोष दूसरों पर डाल रहे हैं क्योंकि वे उन्हें रोकने में नाकाम रहे हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि असल में सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप-प्रत्यारोप कर रही है।

दीपू दास की हत्या पर बोले खरगे

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।

आप की वोट बचाओ, संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू - जनता से छीना जा रहा वोट का अधिकार- संजय सिंह

रामपुर। आम आदमी पार्टी (आप) की वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा की रविवार को रामपुर से शुरूआत हुई। इस पद यात्रा के शुभारंभ के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। संजय सिंह ने कहा कि इसी पद यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए है। दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है। नफरत के कारण न दुनिया बन सकती है और न देश बन सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यही सिद्धांत रहा कि पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया। भाईचारे की बात की।

सभी को साथ लेकर चलने की वकालत की। एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की, जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर सम्मान के साथ रहे। आप नेता ने कहा, कि अपनी यात्रा की शुरूआत से पहले हमने गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है, ताकि हमें न्याय की लड़ाई लड़ने की शक्ति मिल सके। हमारी पदयात्रा रामपुर से शुरू होगी, जो मुरादाबाद होते अमरोहा में जाकर समाप्त होगी। राज्य सभा सदस्य ने कहा कि जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तमिलनाडु में 97 लाख वोट काट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन से चार करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जब इतने वोट कट जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। जो अधिकार महात्मा गांधी, बाबा साहब, भगत सिंह, अशफाक उल्ला जैसे महापुरुषों को बदौलत मिला है, उस अधिकारों का क्या होगा। आए दिन भारत के संविधान पर हमला हो रहा है।

आए दिन नफरत फैलाकर लोगों के अधिकार छीने जा रहे है। वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए हम यह पद यात्रा कर रहे है। इसके अलावा जनसभाएं भी करेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज गांधी जी के विचारों को मारा जा रहा है। एक ऐसी सरकार है, जो गोडसे को अपना आदर्श मानती है। जो नफरत फैलाने की बात करती है। उससे लड़ने के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाना होगा।

सीएम योगी ने को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का किया शुभारंभ, बोले - युवा सहकारिता आंदोलन का भविष्य, वितरित किया ऋण

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को युवा सहकार सम्मेलन और यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को ऋण व प्रशस्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का भविष्य है और भविष्य के शिल्पी है। यह सहकारिता सम्मेलन प्रदेश के सामाजिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता से समृद्धि और सहकारिता से आत्मनिर्भरता का जो विजन दिया है।

वो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।